



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I  
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

ms  
28/11/97

सं० 167 ]  
No. 167 ]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 1997/भाद्र 12, 1919  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 1997/BHADRA 12, 1919

उद्योग मंत्रालय  
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )

संकल्प

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1997

**संख्या ए-42012/24/91-व्य. 4.**—आर्थिक उदारीकरण की वचनबद्धता और प्रशुल्क संबंधी मुद्दों के लिए एक स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और देश के वृहत आर्थिक हितों के दृष्टिगत सरकार ने अलग-अलग उत्पादों और अलग-अलग उद्योगों के लिए प्रशुल्क के उपयुक्त स्तर सुझाने हेतु एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

2. इस आयोग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उनकी सहायता अपर सचिव स्तर के एक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जायेगी जिन्हें सचिव-सदस्य के रूप में पदनामित किया जायेगा। आयोग के अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे और इनकी संख्या 3 से 5 के बीच रहेगी तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए इन्हें पूर्णकालिक सदस्यों में परिवर्तित करने का विकल्प होगा। अध्यक्ष और सदस्य प्रशासन, वित्त, अर्थशास्त्र, उद्योग, वाणिज्य, कृषि एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित संगत क्षेत्रों के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में से लिए जायेंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। आयोग में कोर स्टाफ सहित एक सचिवालय होगा और आयोग द्वारा विद्यमान सरकारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों के अनुसार विशिष्ट अध्ययनों इत्यादि के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवायें ली जायेंगी।

3. आयोग एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के पास उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 19 के प्रावधान की तर्ज पर किसी औद्योगिक उपक्रम में नियुक्त किसी व्यक्ति के अधिकार में अथवा उसके नियंत्रण में किसी भी दस्तावेज, पुस्तक, रजिस्टर अथवा रिकार्ड को प्रस्तुत करने और किसी औद्योगिक उपक्रम में नियुक्त किसी व्यक्ति की जांच करने की उपयुक्त प्रशासनिक शक्तियां होंगी जिसका इन पर नियंत्रण हो। आयोग को सरकार और इसके बाहर दोनों के विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों को अनुसंधान कार्यों का अनुबंध देने हेतु आवश्यक लचीलेपन के लिए भी शक्तियां प्रदान की जायेंगी।

4. प्रशुल्क आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित प्रकार से होंगे :

- (1) बेचे-खरीदे गये सामान के संदर्भ में प्रशुल्क निर्धारित करने और सभी प्रशुल्क संबंधी मुद्दों के निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा भेजे गये मामलों पर औद्योगिक और उत्पादन क्षेत्रों, निर्यात और आयात व्यापार तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ निकाय के तौर पर सलाह और सिफारिशें देना।
- (2) सरकार द्वारा भेजे गये मामलों पर सामान तथा उत्पादों के वर्गीकरण और ऐसे सामान और उत्पादों पर लागू प्रशुल्क के संबंध में सलाह देना।

(3) विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत और अन्य देशों की तुलना में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर तकनीकी अध्ययन चलाना ताकि प्रशुल्क निर्धारण हेतु संगत आंकड़े और मानदंड तैयार किये जा सकें।

(4) सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य करना।

(5) अपने कार्यकलापों के संबंध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. ऊपर वर्णित विषयों से संबंधित कोई भी विभाग/मंत्रालय अपने आप अथवा प्राप्त किये गये अभ्यावेदनों/ज्ञापनों, इत्यादि के आधार पर आयोग को संदर्भ भेज सकता है। आयोग के सुचारु रूप से कार्य करने और आयोग के अप्रासंगिक/अनेकानेक संदर्भों के अधिभार की संभावना के निराकरण हेतु औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग प्रस्तावित संदर्भों के विचारार्थ एक लघु समिति गठित कर सकता है। इस समिति में सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, राजस्व सचिव, वाणिज्य सचिव और उस प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव हो सकते हैं जिनसे प्रस्तावित संदर्भ संबंध रखते हों। ऐसे में आयोग उन आवश्यक संदर्भों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो इस समिति द्वारा भेजे जायेंगे और अपनी त्वरित सिफारिशें देगा। सभी प्रासंगिक आंकड़े देते समय सरकार विस्तृत जांच में एक पार्टी के तौर पर कार्य नहीं करेगी।

6. प्रशुल्क आयोग को उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा सेवाएं प्रदान की जायेंगी।

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

### RESOLUTION

New Delhi, the 2nd September, 1997

**No. A-42012/24/91-E. IV.**—In keeping with the commitment to economic liberalisation and to provide an independent body to look into tariff related issues, Government have decided to constitute an independent Tariff Commission to recommend appropriate levels of tariffs for different products and different industries, keeping in view the larger economic interests of the country.

2. The Commission will be headed by a full-time Chairman of the rank of Secretary to the Government of India and assisted by a full-time member to be designated as Member-Secretary in the rank of Additional Secretary. The other members of the Commission will be part-time members whose number may vary between 3 and 5 with the option to convert some of the part-time members into full time members depending upon exigencies of work. The Chairman and members will be drawn from persons of eminence from relevant fields including administration, finance, economics, industry, commerce, agriculture, and science and technology. The initial appointment of the Chairman will be made for a term of 3 years. The Commission will have a Secretariat with core staff and will engage the services of experts and consultants for specific studies, etc. as per the existing Government guidelines and instructions.

3. The Commission would function as an independent expert Committee. The Chairman and the Member-Secretary would have appropriate administrative powers to order the production of any document, book, register or record in the possession of or power of any person having the control of or employee in connection with, in an industrial undertaking on the lines of the provision of Section 19 of Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and to examine any person having the control of or employed with in connection with, in an industrial undertaking. The Commission will also be empowered with the necessary flexibility to sub-contract research work to specialised agencies both within the Government and outside.

4. The terms of reference of the Tariff Commission shall be as follows:—

- (i) To render advice and make recommendations as an expert body, on matters referred to it by Government regarding fixation of tariff and all tariff related issues in relation to traded goods, keeping in view the interest of the industrial and production sectors, export and import trade and consumers.
- (ii) To render advice on issues referred to it by Government on classification of goods and products along with the applicable tariffs on such goods and products.
- (iii) To carry out technical studies on cost of production of different goods and services and their competitiveness in relation to other countries so as to generate data and parameters relevant to tariff fixation.
- (iv) To undertake such other tasks as may be assigned by Government from time to time.
- (v) To present an annual report to Government of its activities.

5. Any Department/Ministry concerned with the subjects mentioned above may make a reference to the Commission either on its own or on the basis of representations/memoranda, etc. received by them. To facilitate the smooth functioning of the Commission and to obviate possibilities of over-burdening the Commission with unrelated/multiple references, the Depart-

ment of Industrial Policy and Promotion may constitute a small committee to look into the proposed references. This Committee may consist of the Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Revenue Secretary, Commerce Secretary, and Secretary of the Administrative Ministry/Department to whom the proposed reference relates. The Commission would concentrate on need based references referred by this Committee and give its expeditious recommendations. While providing all relevant data, Government would not function as a party to the detailed examination.

6. The Tariff Commission will be serviced by the Department of Industrial Policy and Promotion under the Ministry of Industry.

ASHOK KUMAR, Joint Secy.

